

विनियोग संख्या 62 - भारत का उच्चतम न्यायालय
APPROPRIATION No. 62-SUPREME COURT OF INDIA

			कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
राजस्व:	Revenue:				
प्रभारित-	<i>Charged-</i>				
मूल	<i>Original</i>	43,27,00	52,00,00	48,89,80	-3,10,20
पूरक	<i>Supplementary</i>	8,73,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>				3,08,00

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. विनियोगमें, कुल बचतें (310.20 लाख रु.) मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 873.00 लाख रु. के पूरक विनियोग का 36 प्रतिशत और कुल स्वीकृत विनियोग का 6 प्रतिशत थीं।

1. In the appropriation, the overall savings (Rs.310.20 lakhs) constituted 36 percent of the supplementary appropriation of Rs.873.00 lakhs obtained in March, 2007 and 6 percent of the total sanctioned appropriation.

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष '2014'	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	4327.00	4892.00	4889.80	-2.20
पू.	S.	873.00			
पु.	R.	-308.00			

(I) "उच्चतम न्यायालय - स्थापना" के अंतर्गत 4327.00 लाख रु. के मूल विनियोगको 873.00 लाख रु. का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर 5200.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो ई-समिति द्वारा उपयोग न किए जाने, रजिस्ट्रारों को बकाया राशियों की अदायगी न किए जाने तथा वित्त मंत्रालय से विभागीय कैंटीन का ग्रेड बढ़ाने से संबंधित सूचना प्राप्त न किए जाने के कारण 310.20 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Supreme Court - Establishment" - the original appropriation of Rs.4327.00 lakhs was augmented to Rs.5200.00 lakhs by obtaining supplementary appropriation of Rs.873.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.310.20 lakhs - due to non-utilisation by E-Committee, non-payment of arrears to Registrars and non-receipt of intimation regarding upgradation of Departmental Canteen from the Ministry of Finance.